THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) The State Government reported an expenditure of Rs. 1785.27 lakhs. On the basis of eligible expenditure, advance plan assistance of Rs. 1530.00 lakhs and an amount of Rs. 12.50 lakhs as a part of Central share of margin money were released to the State Government.

गेहूं की वसूली

1370. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के लिए गेहूं की वसूली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य क्या था तथा सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी वसूली की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं उत्पादन में कुछ गिरावट आई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कम वसूली किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन परि-चालनों के अधीन की जाती है । अतः वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । चालू विपणन मौसम के दौरान, 29 जुलाई, 1988 तक 65.17 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है ।

(ग) अनन्तिम अनुमान के अनुसार 446.2 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन होगा जबकि पिछले वर्ष 455.7 लाख मीटरी टन गेहूं का उत्पादन हुआ था ।

(घ) इस वर्ष वसूली पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है । इसके कारण कम उत्पादन होना, बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक होना और व्यापारियों तथा मिल मालिकों द्वारा अधिक खरीद-दारिया करना है ।

गेहूं की वसूली

1371. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा की गई गेहूं की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने गेहूं की बकाया मात्रा का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक आटा मिल को 240/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं देगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या आटा मिल मालिकों ने इस घोषणा के किये जाने के कारण किसानों से वसूली मूल्य से ज्यादा मूल्य पर गेहूं की खरीद की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) गेहूं की वसूली मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन की जाती है । अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ख) सरकार ने बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से 2.0